Assurance w.e.f. 1st February, 1970 and certain other Without-Profit Plans w.e.f. 1st March, 1971. The permium rates under One Year Renable Group Term Assurance plan and Level Group Term Assurance Plan were reduced with effect from 1st June, 1971. The rates applicable to Annuity Plan have been liberalised with effect from 1.3.1972. These reductions were effected after detailed review. The review indicated that in view of the uncertainty of the trend of future expenses, it was desirable to defer consideration of any revision of premium rates under With-Profit Plans till such time as expenses have stabilised.

2. The LIC is alive to the need of keeping its expenses within reasonable limits and has taken, inter-alia, the following steps.

(i) The cadre strength of the administrative staff has been frozen at the level obtaining on 1-4-1974.

(ii) A detailed exercise has been made to simplify procedures so that the offices can cope with increased volume of work without increase in staff strength.

(iii) The budgetary control over expenses has been tightened up

दिल्ली में बिक्री-कर प्रणाली

8450. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की बिक्री-कर प्रणाली अन्य राज्यों की प्रणालियों से भिन्न है ,

(ख) क्या दिल्ली में लागू आखिरी बार (लास्ट प्वाइंट) बिक्री-कर प्रणाली की वजह से बहुत गडबडी होती है , और

(ग) क्या इससे पडौसी राज्यों को भी बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :(क) संविधान की सातवी अनुसूची की सूची-11 की प्रविष्टि 54 के अनुसार एक राज्य के भीतर होने वाली वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाना राज्य सरकार का विषय होने से विभिन्न राज्यो ने अपनी स्थानीय आवश्यकताओ के आधार पर बिक्री-कर की अलग-अलग प्रणालियां अपनाई हुई है ।

(ख) और (ग) : दिल्ली में सामान्यत: बिक्री-कर उपभोक्ता पर बिक्री की अन्तिम स्थिति में उपभोक्ता को बिक्री पर लगाया जाता है । परन्तु कुछ वस्तुओं पर दिल्ली में निर्माता / आयातक द्वारा प्रथम बिक्री पर भी कर लगाया जाता है । बहुत कुछ इसी तरह की व्यवस्था दिल्ली के निकटवर्ती पजाब और हरियाणा राज्यों में भी प्रवर्तमान है । सरकार को नही पता है कि इस वजह से पडौसी राज्यो को कोई बड़ी असुविधा हो रही है ।

नागपुर के सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क समाहर्ता के पास विचाराधीन पड़े मामले

8451. **श्री हुकुम चन्द कछवाय** : क्या वित्त मन्त्री नागपुर के सीमाशुल्क तथा उत्पादशुल्क समाहर्ता के पास विचाराधीन पडे मामलो के बारे में 21 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न सख्या 4369 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागपुर के सीमाशुल्क तथा उत्पादशल्क कार्यालय द्वारा वर्ष 1972 से मार्च, 1975 तक कितने मामलों में फर्मों तथा व्यक्तियो पर जुर्माना करने तथा माल जब्त करने के निर्णय किये गये ; और

(ख) ऐसे कितने मामले है जिनमें लोगों को बिना जुर्माने तथा सजा के ही छोड़ दिया गया तथा इन मामलों पर निर्णय लेने मे कितना समय लगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखार्जी): (क) तथा (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स कोहिनूर मिल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन शुल्क का भुगतान

8452. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या वित्त मन्त्री मैसर्स कोहिनूर मिल्स लिमिटेड, बम्बई, द्वारा केन्द्रीय विक्रय-कर और उत्पादनशुल्क का भुगतान करने के बारे में 21 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स कोहिनूर मिल्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा वर्ष 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान उत्पादन शुल्क की कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(ख) क्या उन्होंने प्रतिवर्ष उत्पादन शुल्क का समय पर भुगतान किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखार्जी): (क) मैसर्स कोहिनूर मिल्स लिमिटेड बम्बई ने वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मद में निम्नलिखित रकमें जमा की हैं :—

वर्ष	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की रकम
	(करोड़ रु०)
1972–73	1.20
1973–74	1.28
1974–75	1.35

(ख) जी, हां।

695 LS—7.

अपोलो होटल, कोलाबा, बम्बई की बिक्री की राशि

8453. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री अपोलो होटल कोलाबा, बम्बई की बिक्री की राशि के बारे में 7 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2713 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपोलो होटल कोलाबा, बम्बई की बिक्री की राशि सहित सब अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को उक्त जानकारी एकत्र करने में क्या कठिनाइयां हो रही हैं और इस बारे में आंकड़े उपलब्ध कराने में सरकार को और कितना समय लगेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) से (ग) : पर्यटन विभाग ऐसे होटलों से, जोकि इसकी अनुमोदित सूची पर नहीं है, बिक्री की राशि आदि के बारे में सूचना नहीं मांगता है। अपोलो होटल पर्यटन विभाग का अनुमोदित होटल नहीं है।

सुनीता चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर

8454. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुनीता चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड जवाहर मार्ग, इन्दौर की इस समय अलग-अलग राज्यों में तथा मध्य प्रदेश के भिन्न-भिन्न नगरों में कितनी शाखाएं कार्यरत हैं और ये शाखायें अलग-अलग नगरों में किन-किन नामों से काम कर रही हैं ;